Regarding welfare measures for farmers ? Laid

श्री हनुमान बेनीवाल **(**नागौर**) :** कृषि मंत्री जी का ध्यान 21 नवम्बर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उच्च स्तरीय समिति की अंतरिम रिपोर्ट की तरफआकर्षित करना चाहूंगा जिसने किसानों की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देते हुए किसानों की कर्ज माफी व एमएसपी को क़ानूनी मान्यता देने तथा रोजगार सृजन के उपाय करने की सिफारिश की है, ठहरे हुए उत्पादन और घटती आय ने किसानों के सिर पर कर्ज का बड़ा बोझ डाल दिया और समिति के अनुसार 30 वर्षो में 4 लाख से अधिक किसान व खेतिहर मजदुर आत्महत्या कर चुके है जो इस बात का प्रमाण है की देश के किसानों की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार की जरुरत है ।

सिर्फ खेती-किसानी से होने वाली आय को गिना जाये तो एक किसान रोज केवल 27 रूपये ही अर्जित कर पा रहा है और इतनी कम आय में खेतों में काम करना व जीवन यापन करना मुश्किल ही नहीं नामुमिकन है,चूँकि किसानों ने भी इन मांगो को लेकर आंदोलन किया इसलिए राजस्थान सहित देश के किसानों की कर्ज माफी करने,एमएसपी को कानूनी मान्यता देने तथा कृषि विपणन प्रणाली में सुधार करने हेतु तत्काल निर्णय लिया जाए ताकि देश के अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके ।

———